



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259343
CG-DL-E-11122024-259343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4963]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946

No. 4963]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

का. आ. 5362(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची के मद 2 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय सरकार भारत की अधिसूचना संख्या का.आ. 2250(अ), तारीख 12 जून, 2024 द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 15 जून, 2024 से छह माह की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा की प्रास्थिति छह माह की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग उद्योग में लगी हुई सेवाओं को 15 दिसंबर, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/05/97-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th December, 2024

S.O. 5362(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the Banking industry, which is covered under item 2 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 15th June, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2250(E), dated the 12th June, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the Banking industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 15th December, 2024.

[F. No. S-11017/05/97-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.